

विचार बिन्दु

पुरुषार्थ से दरिद्रता का नाश होता है, जप से पाप दूर होता है, मौन से कलह की उत्पत्ति नहीं होती और सजगता से भय नहीं होता। –चाणक्य

परंपरा और तकनीकी मिलकर गढ़ रहे हैं नया राजस्थान

राजस्थान, जो कभी रेगिस्तानों और किलों की भूमि के नाम से जाना जाता था, आज परंपरा और तकनीकी के अनोखे संगम से एक नया स्वरूप धारण कर रहा है। यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत आधुनिक विज्ञान के साथ जुड़कर न केवल आर्थिक प्रगति को गति दे रही है, बल्कि युवा पीढ़ी को भी अपनी जड़ों से जोड़े हुए है।

यह संयोजन राजस्थान को वैश्विक पटल पर एक अनूठा राज्य बना रहा है, जहाँ ऊँटों के मेलों के साथ डिजिटल स्टार्टअप्स फल-फूल रहे हैं। परंपरागत हस्तशिल्प अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक रहे हैं, और प्राचीन लोकगीत डिजिटल संगीत ऐप्स में गूँज रहे हैं।

राजस्थान की परंपराएँ सदियों पुरानी हैं, जो लोककला, संगीत, नृत्य और वास्तुकला में झलकती हैं। यहाँ के त्योहार जैसे पुष्कर मेला या जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल रंग-बिरंगे परिधानों, कठपुतली नृत्य और भोपा गायकों से सजेते हैं। महिलाएँ पनहारी गीत गाते हुए कुर्रें से पानी भरती हैं, जो उनकी दैनिक जीवन की कविता है। किले जैसे आमेर, मेहरानगढ़ और जैसलमेर का स्वर्ण किला पीले बलुआ पत्थरों से चमकते हैं, जो राजपूत शौर्य की गाथा कहते हैं।

इन परंपराओं में हस्तशिल्प का विशेष स्थान है। टाई-डाई, मिरर वर्क, ब्लॉक प्रिंटिंग और जरी कढ़ाई जैसी कला पीढ़ियों से चली आ रही है। बीकानेर की कठपुतलियाँ और जोधपुर की लकड़ी की नक्काशी पर्यटकों को लुभाती हैं। राजस्थानी व्यंजन जैसे दाल बाटी चूरमा कम पानी वाली जलवायु के अनुकूल हैं, जो स्थानीय कृषि पर आधारित हैं। ये परंपराएँ न केवल सांस्कृतिक पहचान हैं, बल्कि आजीविका का स्रोत भी। लेकिन बदलते समय में इन्हें तकनीकी से जोड़ना आवश्यक हो गया है।

तकनीकी क्रांति ने राजस्थान को तेजी से बदल दिया है। राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्रों का जाल बिछा है, खासकर फलोदी और जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में, जहाँ सूरज की प्रचुरता का लाभ उठाया जा रहा है।चंबल और माही नदियों पर बांधों से सिंचाई और बिजली मिल रही है, जो कृषि को आधुनिक बना रही है। जयपुर और जोधपुर में आईटी हब विकसित हो रहे हैं, जहाँ स्टार्टअप्स फल-फूल रहे हैं।

सौमेट उद्योग में राजस्थान देश में प्रथम है। लाखेरी और बूंदी के अलावा वर्तमान में सभी सीमेंट कारखाने अब उन्नत तकनीक से चलते हैं। कान्च उद्योग भी फलोदी, जयपुर और धौलपुर में पनप रहा है। डिजिटल इंडिया के तहत राजस्थान में ई-गवर्नेंस मजबूत हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएँ पहुँच रही हैं। मोबाइल ऐप्स से किसान फसल बेच रहे हैं, और ड्रोन से खेतों की निगरानी हो रही है।

यह संयोजन सबसे सुंदर रूप में पर्यटन में दिखता है। प्राचीन किले अब वर्चुअल रियलिटी से जुड़ गए हैं। जयपुर का हवा महल या आमेर किला पर्यटक ऐप्स पर 360 डिग्री दूर देते हैं। पुष्कर मेला लाइव स्ट्रीमिंग से वैश्विक दर्शकों तक पहुँच रहा है। जैसलमेर के घरों में परंपरागत डिवाइन के साथ सोलर पैनल लगे हैं, जो बीकानेर के एक घर का उदाहरण है जहाँ पुरानी वास्तुकला और आधुनिक तकनीक का संगम है।

हस्तशिल्प को तकनीकी ने नई उड़ान दी है। राजस्थानी ब्लॉक प्रिंट अब ऑनलाइन मार्केट्स

जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर बिकता है। डिजाइन सॉफ्टवेयर से आर्टिस्ट्स नए पैटर्न बना रहे हैं। जोधपुर की वुडन क्राफ्ट को 3डी प्रिंटिंग से मजबूती मिल रही है।

ई-कॉमर्स ने स्थानीय कारीगरों को वैश्विक बाजार से जोड़ा है। उदाहरणस्वरूप, राजस्थानी साफा और

जुतियाँ अब डिजिटल कैटलॉग्स में हैं, जो

युवाओं को परंपरा से जोड़ते हैं।

कृषि क्षेत्र में यह मेल चमत्कारिक है। राजस्थान सूखा प्रभावित होने के बावजूद

डिजिटल कृषि से बदल रहा है। किसान

ऐप्स से मौसम पूर्वानुमान पाते हैं, और

ड्रोन से बीज बोया जा रहा है। इंदिरा गांधी

नहर से सिंचाई बढ़ी है, जो परंपरागत खेती

को आधुनिक बनाती है। जैसलमेर के

रेगिस्तान में ड्रिप इरिगेशन से सब्जियाँ उग

रही हैं। जैविक खेती को प्रमोट करने वाले

ऐप्स किसानों को प्रीमियम दाम दिला रहे

हैं। यह न केवल उत्पादन बढ़ा रहा है,

बल्कि जल संरक्षण भी।

शिक्षा में भी परिवर्तन आया है। ग्रामीण स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम हैं,

जहाँ बच्चे टेबलेट पर राजस्थानी

लोककथाएँ सीख रहे हैं। जयपुर के

विश्वविद्यालयों में एआई कोर्सेस

राजस्थानी इतिहास पर आधारित हैं।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से युवा कठपुतली कला या लोकनृत्य सीख रहे हैं। यह परंपरा को जीवंत

रखते हुए भविष्य की तैयारी करा रहा है। उदाहरण के लिए, भोपा गीतकार अब यूट्यूब पर अपनी प्रस्तुतियाँ अपलोड कर रहे हैं, जो लाखों व्यूज पा रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी ने क्रांति ला दी। टेलीमेडिसिन से दूरदराज के गाँवों में डॉक्टर

पहुँच रहे हैं। जोधपुर के एम्स में एआई से डायग्नोसिस हो रहा है। आयुर्वेद को डिजिटल

प्लेटफॉर्म पर प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ प्राचीन जड़ी-बूटियों आधुनिक रिसर्च से सिद्ध हो

रही हैं। कोविड काल में राजस्थान ने डिजिटल हेल्थ ऐप्स से लाखों को बचाया।

सांस्कृतिक संरक्षण में डिजिटल अभिलेखागार महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान सरकार ने विरासत

को डिजिटाइज किया है। किलों की स्कैनिंग से 3डी मॉडल बने हैं, जो भूंकप जैसी आपदाओं से

बचाव करेंगे। लोक संगीत को डिजिटल स्वरूप में संग्रहीत किया जा रहा है। एनजीओ और स्टार्टअप्स

मिलकर राजस्थानी बोलियों को ऐप्स में ला रहे हैं। इससे युवा अपनी भाषा नहीं भूलेंगे।

आर्थिक प्रभाव गहरा है। तकनीकी ने रोजगार सृजित किए हैं। आईटी क्षेत्र में हजारों युवा

कार्यरत हैं। ई-कॉमर्स से हस्तशिल्प निर्यात बढ़ा है। सौर ऊर्जा से ग्रामीण क्षेत्र आत्मनिर्भर बने

हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत राजस्थानी उद्यमी उभर रहे हैं, जो परंपरागत उत्पादों को ब्रांड बना

रहे हैं। उदाहरणस्वरूप, मोम्बतत मराजानी जैसी ब्रांड्स बेलेंस गाउन को ग्लोबल बना रही हैं।

चुनौतियाँ भी हैं। डिजिटल डिवाइड ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहाँ इंटरनेट कमजोर है। परंपराओं का

व्यावसायिकीकरण उनकी शुद्धता को प्रभावित कर सकता है। युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे

हैं। लेकिन सरकार की योजनाएँ जैसे राज-ई-नित्र और डिजिटल गांव इनसे निपट रही हैं।

परंपरा और तकनीकी का यह संगम राजस्थान को सशक्त बना रहा है। यह न केवल आर्थिक

विकास ला रहा है, बल्कि सांस्कृतिक निरंतरता भी सुनिश्चित कर रहा है। भविष्य में एआई और

वर्चुअल दूरिज्म से राज्य चमकेगा। राजस्थान अब रेत के टीलों से आगे, डिजिटल रेगिस्तान का

राजा बन चुका है।

यह प्रक्रिया समावेशी है। महिलाएँ ई-लर्निंग से सशक्त हो रही हैं। आदिवासी समुदाय

डिजिटल मार्केटिंग से अपनी कला बेच रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण में स्मार्ट सेंसर रेगिस्तान को

हरा बना रहे हैं। राजस्थान का यह नया स्वरूप प्रेरणादायक है।

वर्तमान समय में परंपरा तकनीकी को जोड़े है, और तकनीकी परंपरा के पंखा दोनों मिलकर

राजस्थान को विश्व गुरु बना सकते हैं। युवाओं को इस संगम को अपनाना चाहिए। यह नया राजस्थान

सिर्फ राज्य नहीं, एक विचार है जहाँ अतीत और भविष्य एक साथ चलते हैं।

–अविनाश जोशी,

अतिथि संपादक

वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार

राज्यपाल का अभिभाषण: विकसित राजस्थान की दिशा में सशक्त और सुनियोजित पहल

अभिभाषण में इस बात पर विशेष बल दिया है कि शासन की सफलता का वास्तविक पैमाना अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में आने वाला सकारात्मक परिवर्तन है



डॉ. अरुण चतुर्वेदी

सोलहवीं राजस्थान विधानसभा के

पंचम सत्र में राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत

अभिभाषण राज्य के विकास, सुशासन

और जनकल्याण के प्रति सरकार की

प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतिबिंब है। यह

अभिभाषण प्रदेश की वर्तमान

उपलब्धियों, नीतिगत प्राथमिकताओं

और भावी दृष्टि का समग्र, तथ्यपरक

और परिणामोन्मुख दस्तावेज है। इसमें

स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व

में राजस्थान सरकार सेवा, सुशासन

और समावेशी विकास के मूल मंत्र को

धरातल पर उतार रही है।

अभिभाषण में लोकतांत्रिक मूल्यों

की गरिमा को रेखांकित करते हुए इस

बात पर विशेष बल दिया गया है कि

शासन की सफलता का वास्तविक

पैमाना अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के

जीवन में आने वाला सकारात्मक

परिवर्तन है। इसी दृष्टि के अनुरूप राज्य

सरकार ने विगत दो वर्षों में प्रशासनिक

परदर्शिता, जवाबदेही और निर्णयों की

गति को सुदृढ़ किया है। प्रतियोगी

परीक्षाओं की पवित्रता सुनिश्चित करने

के लिए एसआईटी के माध्यम से सख्त

कार्रवाई की गई। परिणामस्वरूप पिछले

दो वर्षों में पेपर लीक की एक भी घटना

सामने नहीं आई। भर्ती प्रक्रियाओं में

अनियमितताओं पर कठोर रुख अपनाने

हुए 140 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज

कर 420 आरोपियों की गिरफ्तारी की

गई, जिससे युवाओं के मन में विश्वास

की पुनर्स्थापना हुई।

युवाओं के भविष्य को सुरक्षित

और सशक्त बनाना राज्य सरकार की

सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहा है। इसी

संकल्प के साथ अब तक लगभग एक

लाख युवाओं को सरकारी नियुक्तियाँ

प्रदान की जा चुकी है, जबकि 1 लाख

54 हजार 547 पदों पर भर्ती प्रक्रिया

प्रगति पर है। वर्ष 2026 के लिए एक

लाख सरकारी पदों का भर्ती कैलेंडर

जारी किया जाना इस बात का प्रमाण है

कि सरकार अवसरों को योजनाबद्ध ढंग

से सृजित कर रही है।

खेलों के क्षेत्र में भी राजस्थान ने

नई पहचान बनाई है। खेलो इंडिया

यूनिवर्सिटी गेम्स-2025 का सात

शहरों में सफल आयोजन हुआ, जिसमें

देशभर के 222 विश्वविद्यालयों के

लगभग 7 हजार खिलाड़ियों ने भाग

लिया। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 49

खिलाड़ियों को 2 करोड़ 95 लाख रुपये

की सहायता प्रदान कर राज्य ने

प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया है।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने समान

अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को केंद्र

में रखते हुए व्यापक सुधार किए हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के

अंतर्गत 2 लाख 37 हजार से अधिक

विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों में

निःशुल्क प्रवेश दिलाया गया, जिसके

लिए लगभग 996 करोड़ रुपये की

प्रतिपूर्ति की गई। वहीं, सरकारी

विद्यालयों में अध्ययनरत 66 लाख से

अधिक विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म एवं

स्कूल बैग उपलब्ध कराने में 482

करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी

के माध्यम से हस्तांतरित की गई।

विगत दो वर्षों में 185 नए

महाविद्यालय भवनों का लोकार्पण, 71

नए महाविद्यालयों की स्थापना और 17

महाविद्यालयों का स्नातकोत्तर स्तर पर

उन्नयन किया जाना राज्य की उच्च शिक्षा

के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

तकनीकी शिक्षा को भविष्य की

आवश्यकताओं से जोड़ते हुए 21 नए

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय प्रारंभ किए

गए तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं

मशीन लर्निंग नीति लागू कर राजस्थान

को तकनीकी नवाचार के अग्रणी राज्यों

की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में

ठोस कदम उठाए गए हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण को

राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते

हुए सरकार ने वित्तीय, संरचनात्मक

और तकनीकी सहयोग को प्राथमिकता

दी है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि

योजना के अंतर्गत 71 लाख 79 हजार

किसानों को लगभग 718 करोड़ रुपये

का भुगतान किया गया। समर्थन मूल्य

पर 21 लाख 37 हजार मीट्रिक टन गेहूँ

की खरीद कर किसानों को 320 करोड़

रुपये का बोनस दिया गया। इसके साथ

ही, अल्पकालीन व्याज मुक्त फसली

ऋण के रूप में 78 लाख से अधिक

लाभार्थियों को 44 हजार 355 करोड़

रुपये वितरित किए गए, जिससे किसानों

की तात्कालिक जरूरतों की पूर्ति के साथ

उनकी आय में स्थायित्व आया है।

महिला सशक्तिकरण और

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी राज्य

सरकार की पहलें प्रभावी सिद्ध हो रही

हैं। 15 लाख 95 हजार महिलाओं को

‘लक्षपति दीदी’ श्रेणी में लाकर उन्हें

आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना

गया है। सामाजिक सुरक्षा पंशान

योजनाओं के अंतर्गत 91 लाख 73

हजार लाभार्थियों को 12 हजार 700

करोड़ रुपये का भुगतान सुनिश्चित किया

गया। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने

के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम

प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 103

करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए

हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण

के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य

योजना राज्य की पहचान बनकर उभरी

है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ 36 लाख

परिवारों को 25 लाख रुपये तक का

कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा

रहा है। विगत दो वर्षों में लगभग 37

लाख रोगियों को 7 हजार 300 करोड़

रुपये से अधिक का निःशुल्क उपचार

प्रदान किया गया। राजस्थान ने अक्षय

ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई

है। फरवरी 2025 में 19 हजार 165

मेगावाट की अधिकतम बिजली मांग

बिना कटौती के पूरी की गई, वहीं

किसानों को 46 हजार 500 करोड़

रुपये की बिजली सब्सिडी प्रदान कर

उन्हें सशक्त बनाया गया है।

समग्र रूप से अभिभाषण इस तथ्य

को रेखांकित करता है कि राजस्थान

सरकार ने विकास को ठोस क्रियान्वयन,

मापनीय परिणामों और जन विश्वास से

जोड़ा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के

नेतृत्व में प्रदेश विकसित भारत-

विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर